श्री चन्द्र पाल शैलानी]

प्रौढ़ शिक्षा पर सरकार करोड़ों रुपया खर्च करती है, किन्तु भट्टा मजदूरों को इससे कोई लाभ नहीं। सरकारी सस्ते राशन की दुकानें वहां नहीं हैं। मजबूरन उन्हें ऊंचे भाव पर गल्ला, चीनी तथा मिट्टी का तेल आदि आवश्यक वस्तुएं बाजार से खरीदनी पड़ती हैं। और तो और पीने के पानी की भी इन मजदूरों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। खुली टंकियों से जानवरों की तरह पानी पीना पड़ता है। मालिक लोग कभी समय पर इन मजदूरों को पैसा नहीं देते और न ही समय पर उनका हिसाब लिखते हैं। यदि किसी मजदूर पर मालिक का पैसा निकलता है तो वह मालिक उस मजदूर के स्त्री बच्चों को बंधक बना कर रख लेता है और अमानुषिक अत्याचार करता है। चूंकि ये ऐसे मजदूर हैं जो साल में आठ महीने अपने वतन से बाहर रहते हैं और चार महीने बरसात में अपने वतन जाते हैं। जब कभी जनगणा होती है या मतदाता सूची में संशोधन होता है और ये मजदूर अपने मूल स्थान पर नहीं मिलते तो मतदाता सूची से इनका नाम काट दिया जाता है और जनगणना में इन्हें शामिल नहीं किया जाता, इस तरह ये लोग भारत के नागरिक ही नहीं रहे। डाक तार की सुविधा भी इन लोगों को नहीं मिल पाती।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि भट्टे पर काम करने वाले मजदूरों की दैयनीय दशा एवं उनके कठोर परिश्रम को ध्यान में रखते हुए इनको ईंट पथाई का रेट बढ़ाकर कम से कम 30 रु० प्रति हजार किया जाय और उपरोक्त वर्णित समस्यायों का समाधान करके उन्हें सभी सुविधाएं प्रदान की जायें।

(vii) DIFFICULTIES OF PEOPLE DUE TO EMPLOYEE'S STRIKE IN BIHAR.

श्रीमती कृष्णा साही (बेगूसराय) : मैं नियम 377 के अधीन लोक महत्व के प्रश्न की ओर मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं।

बिहार राज्य के करीब 6 लाख सरकारी सेवकों, जिनमें प्राइमरी एवं माध्यमिक शिक्षक भी शामिल हैं, दिनांक 12 दिसम्बर 1981 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाने के कारण राज्यभर में कामकाज प्रायः ठप्प हो गया है। प्रशासन पंगु की स्थिति में पहुंच गया है। स्कूलों में पढ़ाई बंद, हस्तालों में मरीजों की दुखद स्थिति का वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। पेयजल शहर में एवं अस्पतालों में बिल्कुल बंद बिजली भी अस्पतालों में बंद, छोटे बच्चे भूखे प्यासे अस्पतालों में हृदयविदारक स्थिति पैदा कर रहे हैं। मरीजों को भोजन एवं दवा देने के लिए एक भी नर्स नहीं है। आपरेशन, फियेटर, महिलाओं के प्रसूति-गृह एवं एमरजेंसी भी प्रायः बन्द पड़े हुए हैं। इन सरकारी कर्मचारियों की अभूतपूर्व हड़ताल के कारण आम जनता के कष्टों का और अन्त नहीं। अतः भारत सरकार से अनुरोध है कि होम गार्ड या एन० सी० सी० या किसी भी अर्द्ध सरकारी संस्थाओं के द्वारा कम से कम अस्पतालों में सेवा उपलब्ध करायें।

(viii) 'ONE DAY CEASE WORK' CALL BY COLLEGE AND UNIVERSITY TEACHERS ALL OVER THE COUNTRY.

SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY (Calcutta South): Sir, the college and University teachers all over the country are observing one day cease work today, at the call of the All India Federation of University and College Teachers Organisations to press their National Charter of Demands, which include:

(1) Solution of problems of DPEs, Librarians, Demonstrators, Assistant Lecturers, Cartographers etc., who have been long denied their dues.

(2) Revision of salary scales, ensuring full neutralisation of erosion in real wages as a result of inflation and single running grade for all categories of teachers.

(3) Statutory security of service for all teachers including those serving in minority-run-institutions.

(4) Representation of AIFUCTO on UGC and CABE.

(5) Democratisation of governance of colleges and Universities.

(6) Full civic and political rights for teachers.

(7) Direct payment from the treasury.

(8) Common cadre for plus II and plus III class teachers.

(9) Abolition of discrimination between teachers of State and Central Universities and colleges affiliated to these with respect of all perquisites.

(10) Age of superannuation not below 60 years.

I, therefore, would like to request the Central Government to accept all these legitimate demands of the teachers, in the interest of higher education.

(ix) SHORTAGE OF KEROSENE OIL IN THE COUNTRY

श्री मनीराम बागड़ी (हिसार) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अधीन लोक महत्व के प्रश्न की ओर मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं :

देश में मिट्टी का तेल मिलता नहीं है, लोग दिन भर लाइन लगा कर खड़े रहते हैं और बाद में निराश हो कर घर वापिस लौट आते हैं। गांव में तो बिल्कुल नहीं मिल रहा है। सभी तेल डिपो वाले धड़ल्ले से ब्लैक कर रहे हैं। इस पर सरकार क्या कारगर कदम उठा रही है ?

(x) DECLARATION OF EMERGENCY IN POLAND

PROF. MADHU DANDAVATE (Rajapur): The declaration of Emergency in Poland is a grave threat to the movement for freedom and democracy and it constitutes an onslaught on all democratic institutions which will be deplored by democrats the world over.

The Military Council set up in Poland has banned strikes and protest meetings, declared martial law and has indefinitely closed all schools and universities. The Government has prescribed all publications Almost all the leaders of Solidarity have been arrested.

The developments in Poland cannot be considered as an internal problem of Poland. The destruction of freedom in one part of the world is always a threat to freedom elsewhere.

I, therefore, request the Minister for External Affairs to make a statement expressing Government's reaction to the declaration of Emergency in Poland.

DR. SUBRAMANIAM SWAMY (Bombay North-East): Sir, I am on a point of order.

(*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: There is a vaccum in the House. And if you want to raise a point of order you must take my permission.

DR. SUBRAMANIAM SWAMY: How is it, Sir? This is a new parliamentary practice. Now, I am seeking permission.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Are you seeking permission?

DR. SUBRAMANIAM SWAMY: Yes.

MR. DEPUTY-SPEAKER: It is all right.